'पहलगाम की छाया में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सभी संभागों व जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिये

जयपुर, 23 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश में सभी जगह माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक विशेष सतर्कता बरतते हुए अपने जिलों में कानून-व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए रखें।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों में विशेष सजगता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल बनाते हुए काम करें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छोटी से छोटी घटना और सूचना को गम्भीरता से लिया जाए तथा तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए।

- **मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों में विशेष सजगता बरतने व सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरन्तर तालमेल रखने के लिये कहा।**
- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने सोशल मीडिया पर गहन निगरानी रखने तथा भ्रामक व आपत्तिजनक टिप्पणियों व अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिये।**

शर्मा ने सोशल मीडिया पर गहन निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि भ्रामक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों तथा अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाए। साथ ही, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से सही सूचना प्रसारित की जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला निंदनीय एवं कायरतापूर्ण घटना है तथा इससे पूरा देश स्तब्ध है। इस जघन्य हमले को अंजाम देने वाला कोई भी आतंकी सुरक्षा बलों से बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों को इस दुःख को सहने के लिए शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की तथा हादसे में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी स्व. नीरज उदवानी के परिजनों से दूरभाष पर वार्ता कर संवेदनाएं व्यक्त की।

पहलगाम के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी स्थानीय की मदद मिली थी। सूत्रों के मुताबिक, आतंकवादी किश्तवाड़ से कोकरनाग होते हुए बैसारन पहुंचे, जिसमें स्थानीय आतंकवादी या हैंडलर ने मदद की। पुलिस ने कई स्थानीय लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम पीड़ितों के लिये दो मिनट मौन रखा

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले पर बुधवार को दुख व्यक्त किया और इसकी कड़ी निंदा की। शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों, वकीलों और अन्य कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर पीड़ितों को अपनी श्रद्धांजलि दी। पूर्ण न्यायालय की बैठक में सर्वसम्मति से आतंकवादी कृत्य की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। शीर्ष अदालत ने एक बयान जारी कर कहा, सर्वोच्च न्यायालय उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिनकी बेरहमी से और समय से पहले हत्या कर दी गई। साथ ही शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता है।

'कश्मीर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को पहलगाम हमले की बर्बरता की जानकारी देगा। पी 5 देशों में चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड तथा अमेरिका शामिल हैं।

भारत सरकार अन्य कूटनीतिक उपायों पर भी विचार कर रही है, जिसमें नई दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिक उपस्थिति कम किये जाने का निर्णय भी शामिल है।

पहलगाम हमले से एनडीए सरकार के इस प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुँचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद कश्मीर घाटी में शांति पुनः कायम हो गई है।

भारत ने पाकिस्तान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बदलने के लिए बांध, नहर और टनल्स बनानी होंगी, जिसमें भारी खर्चा होगा और इनका तुरंत क्रियान्वयन भी संभव नहीं है और इस देरी से पाकिस्तान को समय मिल जाएगा और वह इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा सकता है जिससे भारत का कूटनीतिक गणित गड़बड़ा सकता है।

साथ ही यह कदम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आलोचना को आमंत्रित कर सकता है और शायद इसका वह प्रभाव ना हो जिसकी उम्मीद है।

पाकिस्तान की कृषि व खाद्य सुरक्षा सिंधु नदी पर निर्भर है और पाकिस्तान सिंधु नदी का जल प्रवाह बदलने को लेकर बेहद संवेदनशील है। यदि इस संधि की शर्तों को बदलने की धमकी का इस्तेमाल अकलमंदी से किया जाए तो इसका दीर्घकालिक दबाव डाला जा सकता है।

लेकिन यह मनोवैज्ञानिक दबाव अनपेक्षित विवाद पैदा कर सकता है। इस्लामाबाद इसे अस्तित्व के लिए खतरा बता सकता है, जिस पर तीखी सैन्य व राजनयिक प्रतिक्रिया संभव है। पहले से ही अस्थिर उपमहाद्वीपीय में इस तरह की नीति को सावधानी से हैंडल करने की जरूरत है।

विशेषज्ञों के अनुसार, तुरंत एक बड़ा निर्णय करने की बजाय आई.डब्ल्यु.टी. को दीर्घकालिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के पास ज्यादा प्रभावी तात्कालिक उपाय है।

जैसे कूटनीतिक अभियान चलाकर पाकिस्तान को अलग-थलग करना, टैरर फंडिग को रोकने के लिए फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स को एक्टिव करना और सटीक खुफिया सूचना के आधार पर लक्ष्य साधकर हमले करना।

अगर संधि को रिव्यू भी करना हो तो उसे बदले के तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष हमलों द्वारा शांति के लगातार उल्लंघन के कारण पुनर्विचार के रूप में पेश करना होगा इसके लिए भारत को ना केवल कानूनी रूप से बल्कि नैतिक रूप से मजबूत केस बनाना होगा कि संधि से वे उद्देश्य प्राप्त क्यों नहीं हो रहे, जिनके लिए यह बनाई गई थी।

आई.डब्ल्यू.टी. को निलम्बित करना शायद जनभावना के अनुरूप कड़ा कदम हो, पर सामरिक दृष्टिकोण से यह सीमित लाभ किन्तु दीर्घकालिक खतरों से भरा है और अगर इसमें सोच समझकर रणनीति नहीं बनाई गई तो यह कदम नुकसान दे हो सकता है। नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि धैर्य, बहुकोणीय प्रतिक्रिया ही भारत के दूरगामी सामरिक हित और अंतर्राष्ट्रीय छवि के अनुरूप होगी।

पहलगाम हमले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चीन के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग भी एक और गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था, और सामरिक हितों की समानता, ये सब इस बात की आशंका बढ़ाते हैं कि यह गठबंधन भारत में प्रॉक्सी आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और गहरा हो सकता है।

ऐसे समय में, जब देश मासूम लोगों की मौत का शोक मना रहा है, केन्द्र सरकार पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह इन अहम सवालों के जवाब दे।पहलगाम हमले के पीछे कौन था? आतंकवादी इतनी भारी मात्रा में हथियारों को चुपचाप क्षेत्र में कैसे ला पाए? हमले से पहले हफ्तों तक खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं?

घटना के बाद, पहलगाम और उसके आस-पास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (नैशनल इन्वैस्टिगेशन एजेंसी) और सेना की टीमें हमलावरों की तलाश कर रही हैं।

'आतंकवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो ही रही है। यही वह समय है, जब पर्यटक इस क्षेत्र में घूमने जाते हैं। पर्यटन जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था तथा वहाँ की जनता की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। इस घटना से, इस साल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इस समय भारत सरकार को उनकी मदद करनी चाहिये। इस घड़ी में, हम सब एक हैं। हम आतंकियों के खिलाफ एक रहेंगे।'' इसके साथ ही, कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी सप्ताहो में शुरु होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किये जाने पर भी जोर दिया। सरकारी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि केन्द्र सरकार गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थिति, बढ़ती आय, जनकल्याण और आर्थिक विकास के पूरे दौर को एक झटके में तोड़ दिया है। पूरी प्रक्रिया एक ही प्रहार में रोक दी गई है।

अब बड़ा सवाल यह है कि यह हमला किस हद तक ''नॉन स्टेट एजेन्ट्स'' द्वारा किया गया है या इसके पीछे राज्य का समर्थन है। पहलगाम हमले में, कई मामलों में गाज़ा में इज़रायली नागरिकों पर हमास के हमले जैसी समानताएं हैं। अगर ऐसा है, तो क्या इसके परिणाम भी गाज़ा जैसे हो सकते हैं?

जो सामने आया है, वह यह है कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाकर मारा। उन्होंने सुनियोजित तरीके से निर्दोष पर्यटकों को कश्मीर घाटी में मार डाला। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई।

जिस तरह से आतंकवादियों ने घाटी में इतनी गहराई तक घुसपैठ करके पर्यटकों की खुलेआम हत्या की है, उससे हमारी खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था की खामियाँ उजागर होती हैं। इतना सटीक और सफल हमला, पाकिस्तान सेना के आईएसआई नेटवर्क की विस्तृत मदद के बिना संभव नहीं लगता।

पाकिस्तान को भी इसके नतीजों की चिंता है। उसने कथित रुप से स्वयं को निर्दोष बताते हुए इसे पाकिस्तानी राज्य से असंबंधित घटना बताया है।

पिछली घुसपैठों की तरह, इस बार भी मामले को गंभीरता से लिया गया है। कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक हुई। समिति को घटना की विस्तार से जानकारी दी गई। पच्चीस भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए। आधिकारिक प्रतिक्रिया बेहद संयमित रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) की बैठक हुई। बैठक ढाई घंटे तक चली, जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल व कई प्रमुख अफसरों ने शिरकत की।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सीसीएस की मीटिंग के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

कूटनीतिक कार्रवाइयों के बावजूद, भारत ने सैन्य विकल्प को खुला रखा है। ब्रीफिंग में हमले को स्पष्ट रुप से पड़ोसी देश से जोड़कर देखा गया, जिसके बारे में माना जा रहा है कि, पाकिस्तान के संगठित मंचों द्वारा यह संचालित हुआ है। कई कदमों की घोषणा की गई है। सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान के दूतावास में अब केवल 30 लोग रहेंगे।

यह एक रणनीतिक कदम है। इससे पाकिस्तान को गहरे संकट का सामना करना पड़ेगा। सिंधु नदी जल संधि रद्द होने के साथ ही, 'रन ऑफ द रिवर्स' परियोजनाओं की बैठकें रद्द कर दी गई हैं। अब भारत इन नदियों के जल का प्रबंधन अपने अनुसार करेगा।

पाकिस्तानी रक्षा, नौसेना और वायुसेना के अटैचियों को रद्द कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच सभी प्रकार की आवाजाही बंद कर दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है।

भारत ने यह ठान लिया है कि हमलावरों को सजा दी जाएगी और आगे की कार्यवाही के संकेत नहीं दिए गए हैं।

भारत निश्चित रुप से प्रतिक्रिया देगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया उस समय भारत के साथ खड़ी होगी, जब वह पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाएगा?

एकमात्र जटिलता यह है कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और दुनिया एक परमाणु टकराव की साक्षी नहीं बनना चाहती।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600